



दूध का उत्पादन 1960 में 17-22 मिलियन टन से बढ़कर 2016-17 में 163.7 मिलियन टन हो गया है: श्री राधा मोहन सिंह

श्री राधामोहन सिंह ने डेयरी विकास पर परामर्श हेतु गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता की

Posted On: 28 DEC 2017 5:29PM by PIB Delhi

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि आज भारत विश्व में उस पटल पर पहुँच गया है जहाँ दुग्ध व्यवसाय में वैश्विक स्तर पर उद्यमियों के लिए अनेक संभावनाएँ उभर कर सामने आ रही हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह बात नई दिल्ली में आयोजित डेयरी विकास पर परामर्श हेतु गठित समिति की बैठक में कही।

श्री सिंह ने कहा कि डेयरी विकास हेतु 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं- राष्ट्रीय डेयरी परियोजना-1 (एनडीपी 1), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) तथा डेयरी उद्यमिता विकास योजना।

राष्ट्रीय डेयरी योजना-1:

इस योजना का कार्यान्वयन एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य की सहकारी दुग्ध संगठनों/ दुग्ध फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी):

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य की सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है।

डेयरी उद्यमिता विकास योजना:

इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम विकास बैंक) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा किया जा रहा है।

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि:

दुग्ध किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से तथा श्वेत क्रांति के पूर्व पर्याप्तों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना का कार्यान्वयन एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य की सहकारी दुग्ध संगठनों/दुग्ध फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना हुआ है। इस उपलब्धि का श्रेय दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई अनेक योजनाओं को जाता है। जहाँ 1960 के दशक में करीब 17-22 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वह बढ़कर वर्ष 2016-17 में 163.7 मिलियन टन हो गया है। विशेषकर 2013-14 की तुलना में 2016-17 की अवधि में 19% की वृद्धि हुई है। इसी तरह प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2013-14 में 307 ग्राम से बढ़ कर वर्ष 2016-17 में 351 ग्राम हो गई है जोकि 14.3% की वृद्धि है। इसी प्रकार 2011-14 की तुलना में 2014-17 में डेयरी किसानों की आय में 23.77 % प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत 3 वर्षों में प्रति वर्ष 5.53% की दर से दूध उत्पादन बढ़कर विश्व में दुग्ध उत्पादन की वार्षिक दर से आगे निकल गया है जहाँ दुग्धविकास की दर 2.09% रही है।

श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर विशेषकर भूमिहीन एवं सीमांत किसानों के लिए डेयरी व्यवसाय उनके जीवनयापन एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का जरिया बन गया है। करीब 7 करोड़ ऐसे ग्रामीण किसान परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जिनके पास कुल गायों की 80% आबादी है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की रुचि धीरे धीरे अधिक प्रोटीन वाले उत्पादों की ओर बढ़ रही है एवं वेल्यु एडेड (मूल्य वर्द्धि) उत्पादों का चलन भी बढ़ने के कारण दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है। गत 15 वर्षों में दुग्ध सहकारी संस्थाओं ने अपने कुल उपार्जित दूध के 20% हिस्से को वेल्यु एडेड (मूल्य वर्द्धि) दुग्ध पदार्थों में परिवर्तित किया है जिससे तरल दूध की अपेक्षा 20% अधिक आय प्राप्त होती है। श्री सिंह ने बताया कि ऐसी अपेक्षा है कि वर्ष 2021-22 तक 30% दूध को मूल्य वर्द्धि पदार्थों में परिवर्तित किया जाएगा।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ (वर्ष 2022) तक किसानों की आय को दोगुना करने हेतु किए गए संकल्प के आधार पर डेयरी किसानों की आय को भी दोगुना करने हेतु विभाग द्वारा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस दिशा में डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के दो आधार रखे गए हैं: एक - हमारे दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर आय में वृद्धि कराना एवं दूसरा डेयरी किसानों को दी जाने वाली प्रति किलो दूध की मूल कीमत में वृद्धि करवाना।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमारी कार्यप्रणाली को धीरे धीरे आधुनिक तकनीक वाले वातावरण में बदला जाए। इसी संबंध में विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य योजना विजन 2022 की रचना की जा रही है जिसमें संगठित क्षेत्र द्वारा गाँवों एवं दुग्ध उत्पादकों की संख्या के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए दुग्ध प्रसंस्करण एवं वेल्यु एडेड दुग्ध पदार्थों की मांग को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकताओं के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान रखे गए हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों की आय को दोगुना करना है जो अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण के बगैर संभव नहीं है। इस योजना में यह भी ध्यान रखा गया है कि मौजूद संसाधनों का समुचित विकास एवं उपयोग किया जा सके ताकि इसमें शामिल दुग्ध उत्पादकों सहित सभी हितधारकों को पूर्ण लाभ मिल सके।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री परषोत्तम रूपाला, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्रीमती कृष्णा राज, संसद के सदस्य, डॉ. तापस मंडल (लोक सभा), सुश्री शोभा करंदलाजे (लोकसभा), श्री संजय शामराव धोत्रे (लोकसभा), श्री रोडमल नागर (लोकसभा) और श्रीमती कमला देवी पाटले (लोकसभा) भी बैठक में मौजूद थे।

(Release ID: 1514518) Visitor Counter : 415

